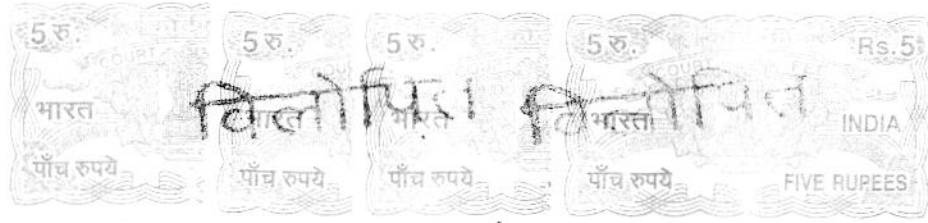
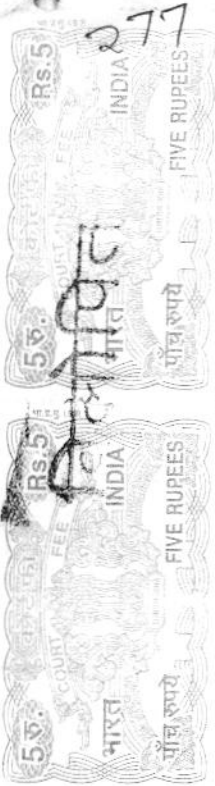


न्यायालय में श्री मान् राजस्वमंडल ग्वालियर म. प्र.



संतु पिता चुट्टनिया कुम्हार निवासी गौम दुलहरा, तहसील मानुषर
जिला उमरिया, म. प्र. ।

III मिशनी/उमरिया/भूदा/2018/0784.... निगरानीकर्ता
बनाम

लहरिया बेबा नंदीलाल कुम्हार सा. दुलहरा, तहसील मानुषर जिला
उमरिया, म. प्र. ।

..... उत्तरवादी

राजस्व निगरानी

अपर कलेक्टर उमरिया

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्र. 72 अ
स्व. निगरानी 15-16 आदेश दिनांक
22.09.16 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 & 11
एम. पी. एल. आर. सी. 1959

चक्र 21 सी. व. के. व. का. म.
1-2-18
प्रस्तुत। प्राप्ति। तर्क हेतु
दिनांक 19-2-18 नियमित।
राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
1-2-18

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निवेदन करता है कि निगरानी का तद्विषय
बिबरण इस प्रकार है कि मौजा दुलहरा के खतरान. 110 के रकबा 18.94 हेक्टा
जो कि म. प्र. शासन राजस्व विभाग जितमे जंगल किस्म दर्ज है जिसे अधिनस्थ
न्यायालय के द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लिया गया था तथा उन्मान
प्रकरण को गुप्त दोष के आधार पर खारिज न करते हुए अस्पष्ट एवं अधूरा आदेश
पारित करते हुए मामला निर्णीत कर दिया गया है जबकि उक्त आराजी म. प्र.
शासन की अमूल आराजी है जो कि 20.70 एकड़ भूमि चरनोई हेतु सुरक्षित
थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया स्वमेव निगरानी
को बैध ठहराते हुए तहसीलदार के आदेश को उचित व नियमतः व्यवस्थापन
होने कालिख किया गया है कि जब कि उक्त आराजी खतरान. नं. के संबंध में
माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा 56 स्व. पुनः आदेश दिनांक 31.07.06
को यह आदेश पारित किया कि उक्त आराजी म. प्र. शासन की आराजी है

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/784

संतू विरूद्ध लहरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 72अ/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	

16.01.19


3

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

3


(आर.के. जैन)
सदस्य
16.01.19